15वाँ स्थापना दिवस समारोह

मार्च 19, 2015

सम्बोधन

माननीय न्यायाधीश गिरिधर मालवीय जी

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय

पासीघाट–791102, अरुणाचल प्रदेश

माननीय न्यायाधीश गिरिधर मालवीय जी

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

15वाँ स्थापना दिवस समारोह के

अवसर पर

माननीय न्यायाधीश गिरिधर मालवीय का सम्बोधन!

1. आदरणीय कुलपति प्रो0 एम0 प्रेमजीत सिंह, प्रो0 एस0एन0 पुरी पूर्व कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल, प्रो0 जी0एन0 पाण्डेय कुलपति, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, नामसाई; सुश्री निधि श्रीवास्तव, उपायुक्त ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो0 ए0के0 पाण्डेय, विशिष्ट अतिथिगण, संकाय सदस्य, महाविद्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रिय छात्रों, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधियों, देवियों एवं सज्जनों!

2. सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय प्रमुख के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस महाविद्यालय के 15वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। यह केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल थी कि उत्तरपूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। इसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित कर 26 जनवरी 1993 को अधिसूचना जारीकर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। इस विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उत्तरपूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के 6

राज्य– अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम एवं त्रिपुरा आते हैं|

3. इस विशेष शुभअवसर पर मैं उन सभी मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत कर पढ़ाई में उत्कृष्ट सफलता पाई है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी वे इसी तरह के परिश्रम एवं उत्साह के साथ अध्ययनरत रहेगें। मैं महाविद्यालय के उस कर्मचारी को भी बधाई देना चाहता हूँ जिसे महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिला है। मैं महाविद्यालय की इन गतिविधियों को देखकर अत्यन्त संतुष्ट हूँ कि महाविद्यालय को जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है उसका अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए वह समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर है । मैं इन उपलब्धियों को प्रत्येक की भागीदारी मानता हूँ जो दिन–रात परिश्रम करते हैं और संस्थान को समृद्ध करते हैं।

4. किसी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लिये मानव संसाधन की समृद्धि नितान्त आवश्यक है और यह कृषि क्षेत्र में विकास के लिये और भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इस संम्बन्ध में देश के उत्तरपूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ। विभिन्न दूरस्थ राज्यों में महाविद्यालयों की स्थापना करके उनके परिसरों में शिक्षा का कार्य सम्पादित करना, वास्तव में एक दूरुह कार्य है। मुझे आज अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यह महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक यात्रा की 14 वर्ष की अवधि पूरी करके दूसरे संस्थाओं के लिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा संस्थान के

रूप में पहचान बना कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे यह बताया गया कि इस संस्था से उत्तीर्ण छात्र–छात्राएं जूनियर रिसर्च फेलो, कृषि अनुसंधान सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी अधिक संख्या में सफल हुए हैं। गत वर्ष जुलाई माह में इस विश्वविद्यालय के छात्रों का जे0आर0एफ0 में उत्तीर्ण छात्रों की द्वितीय स्थान के प्राप्ति के लिये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 एस0एन0 पुरी को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। इस अच्छी उपलब्धि के लिये सभी शिक्षकों, प्रशासकिय एवं अन्य सहकर्मियों को बधाई देता हूँ।

5. मैं अरुणाचल प्रदेश को देश का सजग प्रहरी मानता हूँ जो चीन, म्यांमार एवं भूटान से लगे 1680 किमी0 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी **रखता** हैं। इस कार्य में वह देश के अन्य लोगों के साथ कन्धे–से–कन्धा मिलाकर खड़े हैं। इस प्रदेश को देश के सर्वाधिक हरित प्रदेश के रूप में पहचान की जाती है, जिसमें गैर परम्परागत ऊर्जा के दोहन की अपार संभावनाएं हैं। **साथ ही** जल विद्युत उत्पादन के लिये भी उपयुक्त है। यह प्रदेश जैव विविधता के दृष्टि से विश्व का प्रमुख स्थान है और वर्ष 2012 में इसे 'लोनली प्लेनेट ' द्वारा विश्व के सबसे अच्छे चौथे पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है।

6. मैं यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के एक प्रसिद्ध उद्धरण की चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि **''पृथ्वी के संसाधन हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिये भरपूर हैं लेकिन लालच के लिये नहीं''** यह हम

सभी को संकेत करता है कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सबकी है। देश में आज अनेकों संगठन हैं जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं तथा तमाम खतरों के बावजूद हमारी जैव विविधता आज भी संरक्षित है। जैव विविधिता को संरक्षित रखने में किसानों एवं स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं और उनकी यह अवधारणा वनस्पतियों को पवित्र गुफा के रुप में संरक्षित करने में काफी मदद की है। इसी अवधारणा के तहत् वनों का अधिकांश क्षेत्र अछूता छोड़ दिया जाता है और उसके साथ हस्तक्षेप पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। यह प्रथा ईसा से 3000–5000 पूर्व से व्याप्त है। मुझे ज्ञात हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की कई संस्कृतियाँ प्रचलन में हैं, जिनकी वजह से यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य और हरे–भरे वनों को बनाये रखने में काफी मदद मिली है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में 'नेशनल मिशन फार ए ग्रीन इण्डिया' का भी है। जिसका मुख्य उद्देश्य जंगल की सघनता में वृद्धि करना तथा क्षरित वनों को पुनः समृद्ध करना है। इस मिशन का जंगलों की विविधता एवम् लोगों की आजीविका के ऊपर अनुकूल असर पड़ेगा।

7. मैं जब प्रदेश की शिक्षा का विश्लेषण कर रहा था तब मुझे थोड़ी निराशा हुई कि यह राज्य 66.95 प्रतिशत साक्षरता दर्ज कर देश का नीचे से दूसरा राज्य है; लेकिन जब इसकी पृष्ठभूमि में झाँका तो ज्ञात हुआ कि आजादी के समय इस प्रान्त में मात्र 3 स्कूल थे। वर्ष 1961 में पुरुष

वर्ग की साक्षरता मात्र 7.11 प्रतिशत जबकि महिला साक्षरता 1.42 प्रतिशत थी। विगत दशकों में इस प्रदेश ने शिक्षा की दिशा में सराहनीय प्रगति की है और राष्ट्रीय औसत साक्षरता का अन्तराल जो 10.5 प्रतिशत तथा वह घटकर 7.05 प्रतिशत रह गया है।

मैं इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की पहल को लेकर काफी संतुष्ट हूँ जिसके तहत् केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसके अधीन इस तरह की संस्थाएं विकसित की गयी जो प्रदेश की कृषि, औद्यानिक एवं वानिकी से सम्बन्धित गुणवत्तायुक्त शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं और कुछ एक विषय में स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट तक की उपाधि दे रही हैं।

8. कृषि देश की रीढ़ है और लगभग 60 फीसदी आबादी की आजीविका का भरण–पोषण करती है। देश की सकल घरेलू उत्पाद में 13.9 प्रतिशत कृषि का योगदान है। मैं आजादी के बाद देश में उत्पन्न खाद्य संकट देखा हूँ जिसे 'सिप से माउथ' की संज्ञा दी गयी थी। अर्थात् 'आयातित अन्न से क्षुधापूर्ति' मैं इस सन्दर्भ में अनुसंधानकर्ताओं, योजनाकारों, नितिनिर्धारकों, सभी को बधाई देना चाहता हूँ जिनके सहयोग से देश में हरित क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ और देश खाद्यान्न संकट से मुक्त हुआ। वर्तमान में देश में रिकार्ड खाद्यान्न 263.2 मि0 ट0 का उत्पादन है जो गत वर्ष की तुलना में 6.07 मि0 ट0 अधिक है। देश में चावल का उत्पादन 106.19 मि0 ट0 है। जबकि गेंहूँ का उत्पादन 95.

60 मि0 ट0 है यह दोनों उत्पादन देश में नई कीर्तिमान स्थापित करते हैं।

9. विगत वर्षों में देश में कृषि के अलावा औद्यानिक फसलें जिसमें फल, सब्जियों, पुष्प, सुगंधिय एवं औषधिय फसलें, मसाले तथा रोपड़ फसलें आती हैं उनके ऊपर जोर दिया गया। वर्तमान में औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत लगभग 23.7 मि0 है0 क्षेत्रफल है तथा सकल उत्पादन लगभग 268.8 मि0 ट0 है। वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2011–12 में औद्यानिक फसलोत्पादन में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

10. देश ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और आज सभी के लिये पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद देश की आधी जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त है। वास्तव में यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण न होकर सुक्ष्मतत्व जनित कुपोषण है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महाविद्यालय के शिक्षा एवं अनुसन्धान में प्राथमिकता फल एवं सब्जियों की है जो विटामिन्स आदि के साथ सूक्ष्य तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं जिनका सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण को दूर करने में काफी योगदान है। इस विषय में आप सभी से साझा करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने अभी हाल में ''न्यूट्री फार्म'' नाम से अग्रगामी योजना की शुरूआत की है जिसके अन्तर्गत बॉयो फोर्टीफाइट फूड क्राप्स को उगाने की योजना है। इससे लोगों के पोषण स्तर को समृद्ध करने में मदद मिलेगी। इस योजना को देश के कुल 9 राज्यों के 100 जनपदों में जहाँ

कुपोषण की समस्या है वहाँ शुरू की गयी है। ये कुपोषित राज्य हैं– असम, बिहार, छत्तीसगढ़, म0प्र0, ओडीशा, राजस्थान, उ0प्र0 एवम् उत्तराखण्ड।

11. अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी झूम खेती का प्रचलन है। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि खेती की यह रीति पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नहीं है लेकिन यह मानव सभ्यता काल से चली आ रही है। बहुत कम उत्पादन क्षमता होने के कारण लोगों का इससे वर्ष भर भरण–पोषण भी नहीं हो पाता है। इसे दूर करने के लिये बहुत ही संवेदी एवं संगठित प्रसार व्यवस्था की आवश्यकता है जो इसे दूर कर सके। यह कार्य मैं इस महाविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वे आवश्यकता के अनुरूप तकनीकि का सृजन करें।

12. कृषि उत्पाद अति शीघ्र खराब होने वाली होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्षेत्र से सड़क या रेल मुख्यालय तक लाने का कार्य काफी दुरूह होता है। बिचौलिये इसका लाभ उठाते हैं। तुड़ाई उपरान्त रखरखाव का अभाव **तथा** पैकेजिंग परिवहन आदि का अभाव होने के कारण बहुत अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के बावजूद भी किसान को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। अतः इसके लिये आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे खराब होने वाली वस्तुओं का प्रसंस्करण किया जा सके और बाजार में अधिक उत्पादन होने के बाद अतिरिक्त खाद्य सामग्री का मूल्य संवर्धन किया जाये जिससे उनको अधिक मूल्य मिल सके। भण्डार गृहों में उनको अधिक समय तक सरक्षित करके उचित

समय विपणन की सुविधा उपलब्ध हो। मैं आश्वस्त हूँ कि इस महाविद्यालय का खाद्य प्रसंस्करण विभाग इस सन्दर्भ को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्य संपादित करेगा।

13. जलवायु परिवर्तन सीमा रहित ह, लेकिन इसका महत्व भारत जैसे देश के लिये काफी अधिक है क्योंकि आज भी हमारे देश की अधिकांश खेती मानसून आधारित है। जलवायु की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश बहुत ही संवेदनशील है। अतः यह आवश्यक है कि जो भी पहल करें उसमें नितान्त सावधानी बरतें जिससे इसका प्राकृतिक संतुलन बना रहे। इस सन्दर्भ में कृषि फसलों पर पड़ने वाले अजैविक दवाओं के प्रति उच्च प्रौद्योगिकी एवम् कार्य कुशलता विकसित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह महाविद्यालय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के इस तरह के ज्वलन्त मुद्दों को अपने अनुसंधान सूची में महत्वपूर्ण स्थान देगा।

14. भारत में विश्व की 18 प्रतिशत आबादी है, लेकिन विश्व का मात्र 4 प्रतिशत जल संसाधन है। बढ़ती हुई 1.2 बिलियन आबादी के खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जल की माँग भी बढ़ेगी। साथ ही तेजी से बढ़ती नगरीकरण और औद्योगिकरण जल माँग को और अधिक तीब्र कर दे रहे हैं इससे जल की उपलब्धता एवं माँग की बीच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुनः देश के विभिन्न भागों में असमान वर्षा जल का वितरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके संरक्षण के लिये कुशल क्षमता की आवश्यकता है जो इस प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल कर दे। हम सभी को ज्ञात है कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त मानसूनी वर्षा

होती है; लेकिन यहाँ उगाई गयी जाड़े के मौसम में फसलें सिंचाई की सुविधा न होने के कारण वांछित उपज नहीं दे पाती हैं। वास्तविकता यह है कि पूरे क्षेत्र की मृदा रेतीली है और इसकी जलधारण क्षमता बहुत कम है। मुझे जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि महाविद्यालय द्वारा जल संरक्षण के पालीथीन लेयरिंग करके तालाबों में वर्षा जल को संरक्षित किया गया है। जिसका सूक्ष्म सिंचाई एवं मछली पालन में उपयोग किया जायेगा। इस प्रौद्योगिकी का देश के अन्य क्षेत्र में भी प्रसार की आवश्यकता है जिससे वर्षा जल की कीमती बूँदों को संरक्षित किया जा सके। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिये कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, भी काफी प्रयासरत है। वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत लगभग 4.03 लाख हे0 भूमि को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अन्तर्गत लाया गया है जिसमें 1.99 लाख हे0 भूमि ड्रिप सिंचाई तथा 204 लाख हे0 भूमि स्प्रिन्कलर सिंचाई के अन्तर्गत है।

15. फसल विविधिकरण समय की माँग है। किसान अपने फल, वृक्षों एवं अन्य रोपड़ फसलों की बागान में कम अवधि की सब्जी, मसाला एवं दलहनी सब्जियों को उगाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। मैं इस महाविद्यालय पर तेल ताड़ (Oil Palm) की फसल को देखकर काफी प्रभावित हूँ। ऐसे क्षेत्र जहाँ अन्य फसलों को उगाना कठिन है वहाँ के लिये यह वरदान साबित हो सकती है। पुनः देश में खाद्य तेल का भी काफी अभाव है। इस दिशा में इन उत्तरपूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों में आयल पाम की खेती कर तेल आयात के खर्च को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकता है। इस दिशा में प्रसंस्करण एवम् कार्यक्रम

क्रियान्वयन से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर कारगर पहल करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है इसमें महाविद्यालय अपने अनुसंधान अनुभवों से उत्पादकों को लाभान्वित कर एवम् प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फसल के प्रसार में काफी मदद कर सकता है।

16. टिकाऊ खेती के लिये आवश्यक है कि हम पर्यावरण की गुणवत्ता बनाये रखने के साथ बुनियादी संसाधन जो कृषि के लिये आवश्यक है जैसे जल एवं जमीन को संरक्षित रखें। यह चिन्तायें कृषि की उस प्रणाली के वैकल्पिक रूप को **प्रशस्त** करती हैं जिसमें रसायन मुक्त प्रौद्योगिकी समाहित हे। जैविक उत्पादन प्रणाली ऐसी ही एक वैकल्पिक प्रणाली है। प्रारम्भ में इस खेती के लिये उत्तरपूर्वी राज्यों की पहचान की गयी और इन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में कार्बनिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। इस सन्दर्भ में पहली अच्छी सूचना यह है कि इन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य रसायनों का बहुत अल्प मात्रा में प्रयोग होता है और पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी किसान रसायनों के प्रयोग के प्रति उदासीन भी है। हमारा यह भी मानना है कि हरित क्रांति के प्रभाव से यह पहाड़ी क्षेत्र अछूते रह गये और इनकी उत्पादकता में भी इसी बजह से कमी रह गयी है। इस कमी को जैविक खेती अपनाकर तथा उत्पाद का बढ़ा मूल्य दिलाकर काफी हद तक किसान की आमदनी बढ़ायी जा सकती है। तीसरा प्रमुख पहलू ये है कि यहाँ के प्रत्येक परिवार में लोग सूअर, मुर्गी, बकरी, भैंस, गाय इत्यादि पालते हैं जिससे

पर्याप्त मात्रा में जैविक खेती के लिये कार्बनिक खादों की उपलब्धता रहती है।

17. कृषि के बदलते परिदृश्य में कृषि यंत्रीकरण की नितान्त आवश्यकता है। यह जहाँ उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाता है वहीं उत्पादन लागत कम करके उत्पाद को बाजार में मूल्य स्पर्धा में भी बृद्धि करता है। वर्तमान में प्रयुक्त विजली की खपत लगभग 1.43 किलोवाट/हे0 है। इसे 2 किलोवाट/हे0 तक बढ़ाने की आवश्यकता है इस बृद्धि से गहरी जुताई के यंत्र जैसे चिजलर आदि चलाये जा सकते हैं। हमारे देश के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उ0प्र0 और प0 राजस्थान में विजली की उपलब्धता 1.73 किलोवाट/हे0 है जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में यह काफी कम है और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों का औसत उससे भी बहुत कम। पुनः हर किसान या खेती का उद्यमी इन मँहगे कृषि उपकरणों की खरीद नही कर सकता। इसके लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने केन्द्र पोषित योजना शुरू की है जिसमें 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। इस संदर्भ में 'कस्टम हाइरिंग' सेवा भी शुरू की जा सकती है जिसमें बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा तथा छोटे किसानों को भी सुविधा रहेगी। इस तरह की व्यवस्था कृषि में यंत्रीकरण के कार्य को काफी सरल बना सकती हैं। इन कृषि यंत्रों के रख–रखाव के लिये भी यह आवश्यक है कि हम अपने देश में ही लोगों को प्रशिक्षित करके उद्यमशील बना लें जिसे हमको कहीं और जाने की जरुरत न पड़े।

18. कृषि जैसे उत्पादन उन्मुख क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखी जा सकती है। देश में ऊर्जा की खपत में अभी हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है और विभिन्न कृषि कार्यों के लिये जहाँ पशु एवं मानव श्रम का प्रयोग होता था उसकी जगह ट्रैक्टर जैसे यंत्र लेते जा रहे हैं और सिंचाई के लिये विजली एवं डीजल का प्रयोग होने लगा है। एक आंकलन के अनुसार खेती के विभिन्न कार्यों में विजली एवं ऊर्जा की खपत बढ़कर 86 प्रतिशत हो गयी है जबकि मानव श्रम एवं पशु जनित ऊर्जा का प्रतिशत घटकर क्रमशः 6 एवं 8 प्रतिशत रह गया है। इसमें हमारे नितिनिर्धारकों का ध्यान लक्ष्य के अनुरूप विद्युत उत्पादन कर माँग के अनुरूप आपुर्ति करके कृषि में वृद्धि दर को हासिल करने की होनी चाहिए। इस विषय पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि उपलब्ध ऊर्जा का अच्छी तरह से उपयोग हो और इसमें प्रौद्योगिकी कुशलता हासिल कर और अधिक दक्ष किया जाय। इस दिशा में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत भी काफी उपयोगी हो सकते हैं और उनके दोहन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

19. बाजार में विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों के बारे में त्वरित एवं विश्वसनीय सूचनाएं किसानों को निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करती हैं। वर्तमान सूचना प्रणाली से देश की सभी नियंत्रित मण्डियों को आधुनिक संचार प्रणाली के माध्यम से जोड़कर निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके माध्यम से किसान को अपने उत्पाद को किस मण्डी में विक्री के लिये भेजा जाय इसकी जानकारी

मिल सकती है। इस प्रकार बहुत कम खर्च में संचार प्रणाली का उपयोग कर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था प्रदेश के विभिन्न भागों में सुनिश्चित करे। हमारे यहाँ तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन प्रौद्योगिकी बहुत ही अभाव है तथा प्रसंस्करण की अच्छी प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध नहीं है। मण्डियों में पर्याप्त भण्डारण एवं शीत गृहों की उपलब्धता नहीं है। इन अभावों के चलते काफी क्षति उठानीं पड़ती है और उपभोक्ता को बढ़े दाम देने के लिये विवश होना पड़ता है।

20. विगत वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी एक बहुत ही प्रभावी विज्ञान के रुप में उभर कर सामने आयी है। जिसका उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादन लागत को कम करने में काफी योगदान हे। बी0टी0 कपास की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह प्रौद्योगिकी छोटे किसानों एवं अल्प संसाधन युक्त किसानों के लिये काफी उपयोगी है। कपास जैसी सफलता अन्य फसलों जैसे सोयाबीन, रेपसीड, तोरिया, सरसों, मक्का, धान एवं कुछ सब्जी फसलों में भी लिया जा सकता है। हमको पराजिनी फसलों के बारे में राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निति एवं रोडमैप बनाने की आवश्यकता है। जिससे हमारे किसान इस कारगर प्रौद्योगिकी के उपयोग से वंचित न रह जाँय। जनता की अवधारणा एवम् निर्णय बिना इधर–उधर के, केवल तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिये। अभी जो इस प्रौद्योगिकी के बारे में अन्धविश्वास है वह इस तकनीकि के विकास एवम् कृषि में इसके प्रयोग पर दुष्प्रभाव डालेगा। इस सन्दर्भ में मीडिया एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है, लोगों को ह्रास होते प्राकृतिक

संसाधनों, घटती उत्पादकता एवं बढ़ती आबादी के संदर्भ में इस प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की जानकारी देकर इसे सफल बनाया जा सकता है।

21. पिछले दशक में नैनो प्रौद्योगिकी एक नवीनतम् विज्ञान के रूप में दस्तक दी है। इस प्रौद्योगिकी के तहत् बहुत ही सूक्ष्म कणों जिनका आकार 0.1 से 200 नैनो मीटर होता है उसका उपयोग किया जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग भोजन की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में किया जा सकता है। वर्तमान में इस तकनीकि का प्रयोग करके बहुत से सेंसर विकसित किया जा सकता है, जिनका प्रयोग करके खाद्य श्रृंखला में उपस्थित दूषित पैथोजन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। अरकंसास विश्वविद्यालय में किये गये परीक्षणों से ज्ञात होता है कि कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग करके टमाटर में बीज अंकुरण की वृद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है। सब्जी फसलों में उन्नयन में इस प्रौद्योगिकी के दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

22. कृषि उद्यमी महिला भूमि की तैयारी, जुताई, पौध रोपड़, खरपतवार प्रबन्धन, तुड़ाई एवम् तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, भण्डारण बाजार में विपणन, पशुपालन आदि सभी कार्यों का संपादन करती है। आदिवासी कृषि में महिला मुख्य धुरी होती है। मैं तो इस सन्दर्भ में कहूँगा कि महिला के कार्य की कोई अवधि घण्टों तक ही सीमित नहीं होती, वह हर कार्य को कुशलतापूर्वक करती हैं। आदिवासी पुरुष केवल कुछ मुश्किल के कामों में ही हाथ बटाते हैं। विभिन्न कृषि जन्य वस्तुओं की बिक्री के लिये

महिला अपनी पीठ पर ढो कर लाती हैं। इस सन्दर्भ में महिलाओं के लिये बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं इस प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लिंगअनुपात सामंजस्य के प्रति काफी ध्यान दिया है। यह आँकड़ा संकेत करता है कि किसी लड़की को लिंग के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं किया गया। इससे पूरे देश के एक सीख लेनी चाहिए। मैं इस महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के संख्या अनुपात को देखकर काफी प्रसन्न हूँ जो लगभग 50:50 है।

23. राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे त्वरित तकनीकि बदलाव, आर्थिक और सामाजिक विकास में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप वर्तमान कृषि शिक्षा में बहुत सुधार की संभावना है। उत्पादकता में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास , बढ़ती बेरोजगारी और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में व्यापार में हो रहे उथल–पुथल से उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप अपने कृषि स्नातकों को अपने में एक महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है। वे केवल उपाधि अर्जक ही न हों बल्कि इन समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित कर अच्छा समाधान विकसित करने वाले हों। वर्तमान कृषि शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव की आवश्यकता है जो केवल सार्वजनिक संस्थानों में सेवा हेतु ही न उपयुक्त हों बल्कि उनके अन्दर ऐसे उद्यम कौशलता हो जो स्वयं रोजगार विकसित कर सकें। इस क्षेत्र में कृषि में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। संरक्षित खेती, प्रसंस्करण उद्योग, पशु पालन, मत्स्य पालन में ग्रामीण युवकों एवं युवतियों के लिये रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसमें आवश्यक है कि ऐसी सभी विषयों को अध्ययन के विषय सामाग्री में समाहित किया जाय जो कृषि

विविधिकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था के अनुरूप हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में महाविद्यालय एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा और दूसरों के लिये मार्गदर्शक साबित होगा।

24. एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक विस्तृत आवासीय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक **भारत रत्न पं0 मदन मोहन मालवीय** की **153वीं जयन्ती** के शुभ अवसर पर भारत सरकार ने शिक्षा एवं शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिये 900 करोड़ रुपये की लागत से **पं0 मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन** की शुरूआत की है। यह मिशन शिक्षा के पूर्ण उन्नयन पर केन्द्रित होगा जिसमें 30 स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, 50 सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, 2 इण्टर युनिवर्सिटी सेन्टर फॉर टीचर्स एजूकेशन, एक नेशनल रिसोर्स सेन्टर फॉर एजूकेशन तथा 5 सेन्टरर्स ऑफ एकेडमिक लीडरशिप एवं एजूकेशन मैंनेजमेन्ट खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें पुरस्कार, सेमीनार, कान्फ्रेंस आदि आयोजित करने के लिये प्राविधान किया गया है।

25. डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रयोग की अपार संभावनाएं हैं जिसका हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समुचित उपयोग नहीं कर पायें हैं। ई. लर्निंग तथा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसकी शुरूआत वर्ष 2008 में की गयी थी के माध्यम से कोई विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर पर ही किसी का लेक्चर सुन सकता है, तैयारी कर सकता है और बहुत कम खर्च में डिग्री हासिल कर सकता है। स्वयं एवं Moocs का उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं क्षमता बढ़ाने में प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान सरकार

एवं माननीय प्रधान मंत्री जी ऐसी इलेक्ट्रानिक व्यवस्था को पूरे देश में उपयोग पर बल दे रहे हैं।

26. किसी भी विश्वविद्यालय का असीमित दायित्व होता है और वह समाज के लिये एक रोल मॉडल का कार्य करता है। इसकी प्रेरक शक्ति कक्षा व शिक्षा से परे होती है। अतः इसके प्रभाव का अच्छे **कार्यों** के लिये दोहन करना चाहिये। केन्द्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक महत्व के कई एक विषय से सम्बन्धित पहल की है। **महात्मा गाँधी जी की 150वीं जयन्ती 2019** के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य **स्वच्छ भारत** का है। सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँव के समस्त लोगों के सहयोग द्वारा समग्र विकास की योजना है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 4 फरवरी 2015 कुलपतियों के सम्मेलन में कम से कम 5 गाँवों को सांसद ग्राम योजना के तहत अंगीकृत कर आदर्श गाँव के रुप में बदलने की अपील की है।

मैं अपने कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित मुद्दों को व्याख्यान के समापन से पूर्व आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग धरती माँ की पूजा करना कभी नहीं भूलेंगें क्यूँकि **यह** समस्त सृष्टि की धूरि है। **भूमि** की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। **इस सम्बन्ध में अथर्ववेद के वर्णित पंक्तियां काफी उपयुक्त हैं**

Earth, in which lie the sea, the river and other waters,
in which food and cornfields have come to be,
in which lives all that breathes and that moves,
may she confer on us the finest of her yield.
Earth, in which the waters, common to all,
moving on all sides, flow unfailingly, day and night,
may she pour on us milk in many streams,
and endow us with luster,
May those born of thee, O Earth,
be of our welfare, free from sickness and waste,
wakeful through a long life, we shall become bearers of tribute to thee.
Earth, my mother, set me securely with bliss in full accord with heaven,
O wise one, uphold me in grace and splendor." "**Atharva Veda**"

यहाँ मैं नोबल पुरस्कार से सम्मानित श्री रबिन्द्र नाथ टैगोर की महत्वपूर्ण पंक्तियों को उद्धरित करना चाहूँगा **''उच्च शिक्षा वह हे जो मुझे सूचना ही नहीं अपितु जीवन को सहअस्तित्व के साथ सामंजस्य का बोध कराये'' इससे मिलती ही अरस्तू का विचार है कि ''शिक्षा का प्राथमिक चरण कष्टप्रद दिखता है किन्तु भविष्य खुशियों भरा होता है।''**

मैं महाविद्यालय के 15वीं स्थापना दिवस के आयोजकों को बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे महाविद्यालय के

छात्र–छात्राओं को संबोधित करने के लिये निमंत्रित किया और साथ ही मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का मौका दिया।

महाविद्यालय एवम् विद्यार्थियों द्वारा किये गये गर्मजोशी से भावनात्मक स्वागत एवं इस शैक्षिक आयोजन की स्मृतियों को **मै** सदैव संजोये रखूँगा। धन्यवाद!

जय हिन्द

ACADEMIC BLOCK